

मुख्य समाचार

- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से जुड़ने के लिए केंद्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा— प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों को पहले से अधिक सशक्त बनाने के लिए चिकित्सा सहायक होंगे तैनात।
- प्रदेश में पिछले दिनों हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में लापता लोगों की तलाश अभी जारी— मंडी के तेरंग गांव में एक शव बरामद।
- प्रदेश सरकार ने 10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से एक लाख 87 हजार से अधिक राजस्व मामलों का किया निपटारा।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आम लोगों से जुड़ने, संचार के साधनों का बेहतर उपयोग करने और केंद्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित विशेष सत्र के दौरान आज उन्होंने राज्यपालों की भूमिका पर अपनी प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य में जिला स्तर पर विभिन्न अवसरों के दौरान केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया है। उन्होंने मौके पर ही लोगों की समस्याओं के निवारण के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा—निर्देश दिए हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विभिन्न मामलों पर जनता द्वारा आवश्यक मांगें भी प्राप्त हुईं, जिन पर रेडक्रॉस और विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती रही है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की इस पहल के बाद विभिन्न जिला व राज्य स्तरीय आयोजनों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, निःक्षय मित्र जैसी योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है और आपदा राहत के दौरान भी लोगों से काफी सहयोग प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों को पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और संसाधनयुक्त बनाने के लिए चिकित्सा सहायकों की तैनाती की जाएगी। आज शिमला में टांडा मैडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्नातकोत्तर विषयों में सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश घर्माणी भी मौजूद रहे।

आपदा—बचाव कार्य

प्रदेश में बादल फटने की तीन घटनाओं में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। शिमला जिला के समेज में 36 लोग अभी भी लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खोज अभियान में जुटी एन.डी.आर.एफ की टीम ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए लाईव डिटेक्टर डिवाइस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और स्निफर डॉग की भी सहायता ली जा रही है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि प्रभावित समेज क्षेत्र में चल रहे सर्च ऑपरेशन में तीन सौ एक जवान शामिल हैं। उधर मंडी जिले के पधर क्षेत्र के तेरंग गांव में लापता लोगों को ढूंढने का अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान हादसे वाले स्थान से एक शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि अभी तक कुल 6 शव बरामद हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 4—4 लाख रुपये की राहत राशि दी गई है और उन्हें राशन, मैडिकल किट व तिरपाल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा कुल्लू में 9 लोग लापता हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक लगभग 6 सौ 55 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ है। कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के समेज में सर्च अभियान जोरों पर हैं और लगभग 85 किलोमीटर तक लापता लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। फिलहाल सेना, एन.डी.आर.एफ. एस.डी.आर.एफ. सहित स्थानीय प्रशासन के 400 से अधिक जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज समेज क्षेत्र में घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे प्रभावितों व पीड़ितों से मिले और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। विक्रमादित्य सिंह ने वन विभाग को समेज गांव और गानवी में दो-दो वैली ब्रिज स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और लापता लोगों को ढूँढने के लिए 85 किलोमीटर के क्षेत्र में एन.डी.आर.एफ, एस.डी.आर.एफ, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग के सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस दौरान कैबिनेट मंत्री को खोज एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लोक अदालत

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेशभर में पिछले वर्ष अक्टूबर से इस वर्ष जुलाई के बीच की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से एक लाख 63 हजार 2 सौ 68 इंतकाल, 9 हजार 4 सौ 17 तकसीम, 12 हजार 4 सौ 53 निशानदेही और 2 हजार 4 सौ 27 राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मिशन मोड में कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज विधानसभा की विभिन्न समितियों के सभापति की बैठक शिमला में हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि समितियों के सदस्य अब ऑनलाईन भी बैठकों से जुड़ सकेंगे। पठानिया ने कहा कि इससे समिति के कोरम की समस्या नहीं रहेगी और कार्यों में भी दक्षता आएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का उद्देश्य समितियों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाना है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान एक अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2024 तक के समिति के कार्यों व कियाकलापों और सदस्यों की समिति की बैठकों में सक्रियता पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों से बैठकों में भाग लेने का आग्रह करते हुए इसकी गंभीरता को समझने पर बल दिया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में समावेशी नीतियों के तहत निर्धन वर्गों को राहत प्रदान कर चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। किन्नौर जिला के निवार उपमंडल की मीरू, युला और उरनी के दौरे के दौरान आज उन्होंने ये बात कही। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने विभिन्न जनकल्याणकारी विकास कार्यों के शिलान्यास भी किए। इनमें 2 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले रांगले पुल का शिलान्यास भी शामिल है। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लघु व सीमांत बागवानों को लाभ पहुंचाने व उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन आरंभ कर दिया गया है।

हर्षवर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश के बॉर्डर एरिया में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने व निगरानी बढ़ाने के लिए कांगड़ा जिले के चक्की खड्ड व मंड क्षेत्र में चेक पोस्ट स्थापित करने के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आज नूरपुर में प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ सीमा विवाद के कारण इस क्षेत्र में खनन की अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उद्योग मंत्री ने सभी संबंधित एसडीएम को पंजाब के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि सीमांकन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

सिकंदर कुमार

राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2027 में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वे आज ऊना में केंद्रीय बजट पर आयोजित बुद्धिजीवि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सिकंदर कुमार ने केंद्रीय बजट को आत्म संबल, स्वरोजगारजनित और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में मुद्रा ऋण का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में आसानी होगी। सिकंदर कुमार ने कहा कि इस बजट में हिमाचल के लिए 10 हजार 3 सौ 52 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग मदों में आबंटित की गई है, जबकि रेलवे के आधारभूत ढांचागत निर्माण के लिए पहली बार एकमुश्त 2 हजार 6 सौ 98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

बिंदल भाजपा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा ने बादल फटने की घटना से प्रभावित समेज गांव को फौरी राहत के रूप में ज़रूरत का सामान लोगों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सामान की पहली खेप आज उन्होंने बागी पुल के लिए रवाना कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को ज़रूरी सामान की 10 किटें आज भेज दी गई हैं जबकि 40 और किटें भेजी जाएंगी।